श्री डी० एन० तिवारी : यह सुन कर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि गंडक कमान्ड एरिया में करीब 3 लाख एकड़ जमीन वाटर लाग्ड है । मैं जानना चाहता हूं कि कितनी जमीन की सिंचाई उससे होती है और 3 लाख एकड़ के करीब जो जमीन वाटर लाग्ड है उसमें कुछ होता नहीं है तो उससे कितना नुकसान हर साल होता होगा ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : नुकसान का तो अंदाजा नहीं लगाया गया है कि कितना नुकसान होता है ।

श्री डी० एन० तिवारी : कितने एरिया में सिंचाई होती है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : टोटल सिंचाई कितनी होती है इससे संबंधित यह सवाल नहीं था इसलिए उस के फ़ैक्ट्स नहीं बता सकूंगा । अलग से सवाल करें तो जवाब दूंगा ।

श्री बी० पी० मण्डल : कोसी में जितनी जमीन की सिंचाई होती है उससे ज्यादा जमीन, अच्छी जमीन, डिफ़ेक्टिव ऐलाइनमेंट के कारण वाटर लाग्ड हो जाती है और वही हालत गंडक की भी है । क्योंकि भारत सरकार देश की उपज को बढ़ाना चाहती है, तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस किस्म का जो वाटर लागिंग है, और बिहार सरकार का मैं यह भी कह दूं कि रुपया लैप्स कर जाता है, काम नहीं होता है, तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस में कहां तक इंटरेस्ट लेना चाहती है देश की उपज बढ़ाने के लिये ? वाटर लागिंग की प्रोबलम को दूर करने के लिये आपका पर्सनली कितना इंटरेस्ट है ?

MR. SPEAKER: It is a suggestion.

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल स्टेट सबजेक्ट है इसलिए मैनली स्टेट्स ही स्कीम बनाती हैं और ऐग्जीक्यूट करती हैं और फ़ाइनेंस करती हैं । इसीलिये स्टेट गवर्नमेंट ने यह 42 लाख से बढ़ाकर 27 करोड़ रु० किया है । उन्होंने समझा है कि इस प्रौब्लम को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिये और वह इस काम पर लगी हुई है । जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं बहुत देर से यह मसला है, इसमें बहुत काम अभी तक नहीं हो सकता है । लेकिन अब आगे काम अच्छी तरह से होगा । हम भी इसमें दिलचस्पी लेंगे और स्टेट गवर्नमेंट भी दिलचस्पी ले रही है ।

Payment to re-employed teachers of Aided Schools in Delhi

*460. SHRI BALAK RAM: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the services of some teachers working in Government aided schools of Delhi had been terminated after declaring them as unqualified;

(b) whether it is also a fact that some of the teachers whose services had been terminated were found qualified only after intervention of his Ministry and thus given re-employment;

(c) whether it is also a fact that such teachers have not been paid their emoluments for the above said intervening period which varies from months to years; and

(d) what remedial steps are being taken by the Central Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRIMATI RENUKA DEVI BARAKATAKI). (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

According to information received from Delhi Administration, some aided private schools were found to have recruited certain persons who did not possess the educational qualifications and/or were over-aged, in accordance with the provisions of the Delhi School Education Rules, 1973. Accordingly, the services of such employees had to be terminated. However, representations received from the concerned employees were considered by the Administrator, Delhi, and it was decided, on compassionate grounds, to relax the age limit in favour of those who had been appointed upto the end of December, 1975 and who had completed one year's service. No relaxation was, however, granted in favour of those who did not possess the minimum educational qualifications. There was no occasion for intervention by the Government of India.

The persons in whose favour the age limit was relaxed were reinstated and the period between the termination of service and reinstatement was treated as leave of the kind due. The concerned institutions have also been authorised to disburse the admissible leave salary.

श्री बालक राम : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब जो मंत्री महोदय ने दिया है वह मेरे सावल के जवाब मे तमल्ली गलत नही है, क्योकि टीचरो को गलत आरर्डर देकर 30-11-65 मे लेकर 2-2-67 तक नौकरी से अलग रखा गया अन-क्वालीफाइड का बहाना लगाकर, फिर उसी पोस्ट के अगेन्स्ट उन्हें उसी स्कूल में वापिस लेना पड़ा और टीचरों को बिना गलती पाये तनख्वाह से महरूम रखा गया, जबकि सारी गलती दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की थी । उन्होंने अपनी गलती छिपाने के लिये टीचरों को 14 महीने की तनख्वाह नहीं दी । इसमें एक कोई भी सवाल नहीं था । इस बारे में मैंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को भी कई बार लिखा लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला ।

मैं मंत्री महोदय से एश्योरैंस चाहता हूं कि इस तरह से गलती से निकाले गये टीचरों को क्या उसी तरह की तनख्वाह और एलाउन्सेज की अदायगी की जायेगी और जिन अफसरों ने ऐसी गलती की है, क्या उन्हें जिम्मेदार ठहराया जायेगा ?

SHRIMATI RENUKA DEVI BARAKATAKI: In the Statement which I have laid on the Table of the House, I have clearly stated that some of the aided private schools had appointed some under-qualified teachers, and when the claim for grants came to Delhi Administration, on scrutiny it was found that many of these teachers—not many, but ten—were found under-qualified in respect of educational qualifications and were also overaged. Their services had been terminated. But afterwards when they appealed to the Administrator, at the level of Lt. Governor, a decision was taken to reinstate those teachers to whom relaxation had been given in respect of age; but no relaxation was given to their educational qualifications. Accordingly, the teachers were reinstated. This intervening period between termination of service and reinstatement was taken as leave of the kind due and the concerned institutions were requested to make the payment to the teachers.

श्री बालक राम : दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन मे कुछ ऐसे भी टीचर्स है, जिनको अफसरों ने गलत आज्ञा देकर वक्त से पहले रिटायर कर दिया और उन्हें फिर घर बैठे ही तनख्वाह दी । इस तरह से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरो की मनमानी के कारण जो डबल पालिसी चल रही है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस विषय में भारत सरकार की क्या नीति है ?

SHRIMATI RENUKA DEVI BARAKATAKI: If the hon. Member can bring the specific cases to our notice, then we will examine them.

श्री भागीरथ भंवर : मैं यह जानना चाहता हूं कि निकाले गये अध्यापकों की संख्या कितनी है और कितने लम्बे समय से ऐसा चला आ रहा था कि अयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी ? क्या ऐसी गड़बड़ियों की जांच के लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था है ? जो लोग शासन की ओर से एड लेकर पैसे का दुरुपयोग करते है और नाजायज फायदा उठाते है, इस सम्बन्ध मे जांच के लिये क्या कोई व्यवस्था भी शासन की ओर से है ? यदि है, तो इसकी अभी तक जांच क्यो नही की गई ?

SHRIMATI RENUKA DEVI BARAKATAKI: As we have been informed by the Delhi Administration, the number of teachers whose services were terminated was ten and out of them, eight were reinstated and it was not for years together. The Delhi Administration School Department came into existence in 1974, the Delhi Administration School Education Rules were passed in 1973. In 1976, we decided to reinstate some of these teachers. It was, therefore, not for years, but for a few months only. And for one year, we have given relaxation to them.

श्री राम कंवार बेरवा : मंत्री महोदय ने बताया है कि जो शिक्षक अयोग्य पाये गये, उन्हें निकाला गया है । यह बहुत पुराना मामला है । पिछली सरकार ने काफी टीचरों को राजनीति मे भाग लेने का आरोप लगा कर निकाल दिया था । मंत्री महोदय पिछली लकीर पर चल कर इस प्रकार के जवाब दे रहे है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने पर्सनली रुचि ले कर इस मामले की अच्छी तरह जांच की है । क्या यह सत्य नहीं है कि अयोग्य होने का बहाना बना कर योग्य व्यक्तियों को भी निकाला गया है ? क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि ऐसे शिक्षकों को वापस लिया जायेगा ?

SHRIMATI RENUKA DEVI BARAKATAKI. This question related to the aided schools under the Delhi Administration and not all the schools.

Implementation of Land Ceiling Laws

*461. SHRI HITENDRA DESAI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to lay a statement showing:

(a) how much land has been obtained under the Land Ceiling laws in each of the States and Union Territories; and

(b) when will the implementation of Ceiling laws be completed?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) A statement is placed on the Table of the Sabha.

(b) Implementation of Ceiling laws is the responsibility of State Governments. They have been urged to expedite implementation and to find out methods of overcoming legal and procedural difficulties. It is not possible to indicate any date by which implementation of ceiling laws will be completed.